

खतयान आधारति स्थानीय नीति और ओबीसी आरक्षण वधियक पारति

चर्चा में क्यों?

11 नवंबर, 2022 को झारखंड वधानसभा के विशेष सत्र में राज्य सरकार ने 1932 का खतयान आधारति स्थानीय नीति और ओबीसी आरक्षण वधियक ध्वनमित से पारति करा लया।

प्रमुख बदि

- झारखंड स्थानीय व्यक्तियों की परभाषा और परणामी सामाजिक, सांस्कृतिक और अन्य लाभों को ऐसे स्थानीय व्यक्तियों तक वसितारति करने के लयि वधियक-2022 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सदन में रखा। वपिक्ष की ओर से इसमें कई संशोधन आए, प्रवर समति को भेजने का भी प्रस्ताव आया, लेकनि सरकार ने इसे ध्वनमित से इन्कार कर दया।
- इस वधियक के मुताबकि वे लोग झारखंड के स्थानीय अथवा मूल नवासी कहे जाएंगे, जनिका या जनिके पूर्वजों का नाम 1932 या उससे पहले के खतयान में दर्ज है।
- जनिका नाम खतयान में दर्ज नहीं होगा अथवा जनिका खतयान खो गया हो या नष्ट हो गया हो, ऐसे लोगों को ग्राम सभा सत्यापति करेगी कि वे झारखंड के मूल नवासी हैं या नहीं। भूमहीन व्यक्तियों के मामले में, स्थानीय व्यक्तिकी पहचान ग्राम सभा द्वारा संस्कृति, स्थानीय रीति-रिवाज, परंपरा आदि के आधार पर की जाएगी।
- वधानसभा सत्र के दौरान मुख्यमंत्री ने वधियक में थर्ड एवं फोर्थ ग्रेड की नौकरी को स्थानीयता की नीतिको नयिजन नीति से जोड़ा और कहा कि 1932 का खतयान जनि लोगों के पास होगा, वे लोग ही थर्ड और फोर्थ ग्रेड की नौकरी के पात्र होंगे।
- 1932 के खतयान पर आधारति स्थानीयता का वसितार पूरे झारखंड में होगा। ये अधनियम भारत के संवधान की 9वीं अनुसूची में शामिल होने के बाद प्रभावी होगा।
- स्थानीय व्यक्तियों का अर्थ झारखंड का अधवास (डोमसाइल) होगा, जो एक भारतीय नागरकि है और झारखंड की क्षेत्रीय एवं भौगोलकि सीमा के भीतर है और उसके या उसके पूर्वजों का नाम 1932 या उससे पहले के सर्वेक्षण/खतयान में दर्ज है।
- इस अधनियम के तहत परभाषति स्थानीय व्यक्तिकी सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक बीमा और रोजगार/बेरोजगारी के संबंध में राज्य की सभी योजनाओं और नीतियों के हकदार होंगे तथा उन्हें अपनी भूमि, रोजगार या कृषि ऋण/ऋण आदि पर वशिषाधिकार और संरक्षण प्राप्त होगा।
- इस अधनियम के तहत परभाषति स्थानीय व्यक्तिकी प्राथमकिता के आधार पर अपने भूमि रिकॉर्ड को बनाए रखने के भी हकदार होंगे, जैसा नयिम के तहत निर्धारति और वनियमति कया जा सकता है।
- इस अधनियम के तहत परभाषति स्थानीय व्यक्तिकी राज्य में व्यापार और वाणजिय के लयि वशिष रूप से पारंपरिक और सांस्कृतिक उपकरमों से संबंधति स्थानीय वाणजियकि सांस्कृतिक उपकरमों और स्थानीय झील/नदियों/मत्स्य पालन पर अधमिन्य अधिकार के भी हकदार होंगे।
- इसके अलावा वधानसभा में ओबीसी आरक्षण बलि भी पास हुआ। राज्य में अब 77 फीसदी आरक्षण होगा। पछिड़ा वर्ग (OBC) को 27 फीसदी, अनुसूचति जनजाति (ST) को 28 फीसदी और अनुसूचति जाति (SC) को 12 फीसदी आरक्षण मलैगा।